GEO IAS
It's about quality

9 July 2024

GEO Daily

Daily Current Affairs

GEO IAS

SOURCES

THE HINDU | The Indian EXPRESS JOURNALISM OF COURAGE | pib | AIR | live mint | THE FINANCIAL EXPRESS | ET ECONOMIC TIMES.COM

Date: 9 July 2024

Important News Articles

1. असंगठित क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी दक्षिण भारत में सबसे अधिक-द हिंदू
2. केंद्र सरकार शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए मानदंड में बदलाव करेगी- द हिंदू
3. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने BBNJ समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी- पीआईबी
4. हीरे के आयात में बाधाएं अनुसंधान महत्वाकांक्षा के लिए एक बड़ा अवरोध - द हिंदू
5. सरकार ने श्वेत वस्तुओं हेतु PLI योजना 12 अक्टूबर तक फिर से खोली - द हिंदू
6. सरकार तट से जहाज तक बिजली परियोजना का विस्तार करेगी - द हिंदू

Editorials, Gists and Explainers

7. संस्कृति मंत्रालय ने 46वीं विश्व धरोहर समिति बैठक हेतु प्रोजेक्ट PARI की शुरुआत की - पीआईबी
8. स्वदेशी HPV वैक्सीन से संबंधित मामला - द हिंदू
9. दिल्ली में पेड़ों की कटाई को रोकने वाले कानून -द हिंदू
10. सरकार को स्वास्थ्य बजट को दोगुना करना चाहिए - द हिंदू

Quick Look

1. आनंद विवाह अधिनियम
2. अग्निबाण सबऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोस्ट्रेटर (SOrTeD)
3. परमाणु ऊर्जा आयोग
4. करम्पुआंग गुफा
5. शास्त्रीय भाषा

महत्वपूर्ण समाचार लेख

सामान्य अध्ययन।

1. असंगठित क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी दक्षिण भारत में सबसे अधिक-द हिंदू

प्रासंगिकता: महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या और संबंधित मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक मुद्दे, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके समाधान।

प्रीलिम्स टेकअवे
- असंगठित क्षेत्र

समाचार:
- हाल ही में जारी असंगठित क्षेत्र के वार्षिक सर्वेक्षण वर्ष 2022-23 के अनुसार, असंगठित उद्यमों में महिला मालिकों और श्रमिकों की हिस्सेदारी दक्षिणी राज्यों में अपेक्षाकृत अधिक थी।

मुख्य बिंदु
- कुछ हद तक, कुछ पूर्वी राज्यों में भी इस क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी अधिक थी; पश्चिमी, उत्तरी और मध्य राज्यों में यह कम रही।
- असंगठित क्षेत्र में वे नौकरियां शामिल हैं जिनके लिए बहुत कम या कोई पूंजी और कौशल की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे कि स्ट्रीट वेंडिंग, साथ ही ऐसे काम जिनमें काफी निवेश और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, जैसे कि सिलाई और कार मरम्मत।
- दुकान का संचालन किसी व्यक्ति या स्व-नियोजित उद्यमी द्वारा किया जा सकता है, जो बिना वेतन वाले अपने परिवार के सदस्यों को काम पर रख सकता है या वेतनभोगी कर्मचारियों को नियुक्त कर सकता है।
- ये एक निश्चित स्थान से या घरों, छोटी दुकानों और कार्यशालाओं में काम कर सकते हैं।
- सर्वेक्षण ऐसे श्रमिकों को तीन व्यापक क्षेत्रों में विभाजित करता है: विनिर्माण, व्यापार और अन्य सेवाएं, तथा इसमें कृषि प्रतिष्ठान शामिल नहीं हैं।
- इस क्षेत्र में कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत प्रतिष्ठान और उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठान तथा सार्वजनिक क्षेत्र/सरकारी कंपनियां शामिल नहीं हैं।
- यह चार्ट विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न पदों पर कार्यरत महिलाओं की हिस्सेदारी को दर्शाता है, जैसे अवैतनिक पारिवारिक सदस्य, अनौपचारिक/औपचारिक कामगार, तथा असंगठित उद्यमों में कार्यरत मालिक।
- एक वृत्त एक राज्य को दर्शाता है। क्षेत्रों को रंगों से अलग किया गया है। छोटे राज्यों पर विचार नहीं किया गया।
- चार्ट का भाग 1A, सभी वर्गों के श्रमिकों को मिलाकर, सभी अनिगमित उद्यमों के क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं की हिस्सेदारी को दर्शाता है।
- दक्षिण भारत के बाहर पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है जो इस सूची में उच्च स्थान पर है।
- हालांकि, सामान्य तौर पर, गैर-निगमित उद्यमों में अवैतनिक पारिवारिक श्रमिकों में महिलाओं की हिस्सेदारी प्रत्येक राज्य में अन्य प्रकार की नौकरियों की तुलना में बहुत अधिक थी।
- इसका अर्थ यह है कि भारत भर में महिलाएं असंगठित क्षेत्रों में अपेक्षाकृत शांत, फिर भी प्रमुख भूमिका निभाती हैं।
- कई मामलों में, वे कोई भुगतान नहीं लेते हैं और उद्यम कैसे चलाया जाए, इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं होती।

2. केंद्र सरकार शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए मानदंड में बदलाव करेगी- द हिंदू

प्रासंगिकता: भारतीय संस्कृति - प्राचीन काल से आधुनिक काल तक कला रूपों, साहित्य और वास्तुकला के प्रमुख पहलू।

प्रीलिम्स टेकअवे
- शास्त्रीय भाषाएँ
- लिंगविस्टिक ऑफिसर

समाचार:
- कई भाषाओं को शास्त्रीय दर्जा दिए जाने की मांग के बीच, केंद्र सरकार ने विशेष दर्जा देने के मानदंडों में बदलाव करने का निर्णय लिया है।
- संस्कृति मंत्रालय की भाषाविज्ञान विशेषज्ञ समिति ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें परिवर्तन का सुझाव दिया गया।

मुख्य बिंदु:
- सूत्रों ने बताया कि केंद्र ने पैनल से नियमों पर पुनर्विचार करने को कहा है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद नए मानदंडों की गजट अधिसूचना जारी की जाएगी।
- इसका अर्थ यह है कि कुछ भाषाओं, मुख्यतः मराठी, को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के मामले में सरकार को अधिसूचना का इंतजार करना पड़ सकता है, जो अभी विचाराधीन है।

- पिछले कुछ वर्षों से कुछ राज्य और साहित्यिक मंडल मराठी, बंगाली, असमिया और मैथिली जैसी भाषाओं के लिए शास्त्रीय दर्जा देने की मांग कर रहे हैं।
- वर्ष 2014 में, तत्कालीन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने मराठी भाषा विशेषज्ञों की एक समिति गठित की और रिपोर्ट केंद्र को सौंपी गई।
  - पठारे समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि मराठी शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता पाने के सभी मानदंडों को पूरा करती है।
- केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने फरवरी 2022 में संसद को सूचित किया कि "मराठी को शास्त्रीय दर्जा देने का प्रस्ताव संस्कृति मंत्रालय के सक्रिय विचाराधीन है"।
- एक बार किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में अधिसूचित कर दिया जाता है,
  - शिक्षा मंत्रालय इसे बढ़ावा देने में सहायता करता है, जिसमें भाषा के प्रतिष्ठित विद्वानों के लिए दो प्रमुख वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना करना भी शामिल है।
  - इसके अलावा, भाषा के अध्ययन के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है, तथा
  - विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरोध है कि वह केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में निश्चित संख्या में व्यावसायिक पीठों का सृजन करे।
- महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मराठी भाषा के समर्थन में मांग तेज हो गई है।
- इस समिति का कार्य केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ संपर्क स्थापित करना तथा मामले को आगे बढ़ाना है।

सामान्य अध्ययन II

3. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने BBNJ समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी- पीआईबी

प्रासंगिकता: महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, एजेंसियां और मंच - उनकी संरचना, अधिदेश।

प्रीलिम्स टेकअवे
- UNCLOS
- BBNJ

समाचार:
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत को राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता (BBNJ) समझौते पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दे दी है।
- यह ऐतिहासिक निर्णय राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्य बिंदु:
- राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे के क्षेत्रों को प्रायः 'उच्च सागर' के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो वैश्विक आम महासागर हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैध प्रयोजनों जैसे कि नौवहन, उड़ान, पनडुब्बी केबल और पाइपलाइन बिछाने आदि के लिए सभी के लिए खुले हैं।
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय देश में BBNJ समझौते के कार्यान्वयन का नेतृत्व करेगा।
- भारत पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के वैश्विक उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध और सक्रिय है।
- BBNJ समझौता, या 'उच्च सागर संधि, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (UNCLOS) के अंतर्गत एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है।
  - इसका उद्देश्य समुद्र में समुद्री जैव विविधता के दीर्घकालिक संरक्षण पर बढ़ती चिंताओं का समाधान करना है।
  - यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वय के माध्यम से समुद्री जैव विविधता के सतत उपयोग के लिए सटीक तंत्र निर्धारित करता है।
  - पक्षकार खुले समुद्र से प्राप्त समुद्री संसाधनों पर संप्रभुता का दावा या प्रयोग नहीं कर सकते हैं तथा लाभों का निष्पक्ष और न्यायसंगत बंटवारा सुनिश्चित करेंगे।
- इससे कई सतत विकास लक्ष्यों, विशेषकर सतत विकास लक्ष्य 14 (जल के नीचे जीवन) को प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी।
- साझा मौद्रिक लाभों के अलावा, यह हमारे समुद्री संरक्षण प्रयासों और सहयोगों को और मजबूत करेगा, वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास, नमूनों, अनुक्रमों और सूचनाओं तक पहुंच, क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण आदि के लिए नए रास्ते खोलेगा, न केवल हमारे लिए बल्कि पूरी मानव जाति के लिए लाभप्रद होगा। उन्होंने कहा कि भारत द्वारा BBNJ समझौते पर हस्ताक्षर करना यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है कि हमारे महासागर स्वस्थ और रेसिलिएंट बने रहें।

- BBNJ समझौता, यदि लागू हो जाता है, तो UNCLOS के तहत तीसरा कार्यान्वयन समझौता होगा, इसके साथ ही इसके अन्य कार्यान्वयन समझौते भी लागू होंगे: वर्ष 1994 भाग XI कार्यान्वयन समझौता और वर्ष 1995 संयुक्त राष्ट्र मत्स्य स्टॉक समझौता।
- UNCLOS समुद्र के पर्यावरण संरक्षण और समुद्री सीमाओं, समुद्री संसाधनों के अधिकारों और विवाद समाधान के लिए महत्वपूर्ण है। यह राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे महासागर तल पर खनन और संबंधित गतिविधियों को विनियमित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण की स्थापना करता है।
- आज तक 160 से ज़्यादा देशों ने UNCLOS का अनुमोदन कर दिया है। दुनिया के महासागरों के इस्तेमाल में व्यवस्था, समानता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए यह बहुत ज़रूरी है।
- BBNJ समझौते पर सहमति बन गई है और सितंबर 2023 से शुरू होने वाले दो वर्षों के लिए हस्ताक्षर के लिए खुला है। 60वें अनुसमर्थन, स्वीकृति, अनुमोदन या परिग्रहण के 120 दिन बाद लागू होने के बाद यह एक अंतरराष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि होगी। जून 2024 तक, 91 देशों ने BBNJ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, और आठ पक्षों ने इसकी पुष्टि की है।

सामान्य अध्ययन III

4. हीरे के आयात में बाधाएं अनुसंधान महत्वाकांक्षा के लिए एक बड़ा अवरोध - द हिंदू

प्रासंगिकता: विज्ञान और प्रौद्योगिकी-विकास और उनके अनुप्रयोग और दैनिक जीवन पर प्रभाव।

प्रीलिम्स टेकअवे
- क्वांटम प्रौद्योगिकी

समाचार:
- कस्टम विभाग द्वारा हीरे का आयात कौन कर सकता है और कौन नहीं, इस बारे में लिए गए निर्णय से राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (NQM) की चमक कुछ कम हो रही है।

मुख्य बिंदु:
- राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (NQM), ₹6,000 करोड़ की पहल है, जो भारत को क्वांटम प्रौद्योगिकियों के उभरते क्षेत्र में अग्रणी बनने में मदद कर सकती है।
- क्वांटम प्रौद्योगिकी एक व्यापक शब्द है जो अनुसंधान के अनेक क्षेत्रों पर लागू होता है।
- यह परमाणु के अंदर पदार्थ के "क्वांटम-मैकेनिकल" गुणों का दोहन करने और पूरी तरह से नए प्रकार के कंप्यूटर, सेंसर और एन्क्रिप्शन सिस्टम विकसित करने में सक्षम होने पर निर्भर करता है

हीरे की विशिष्टता
- जहां रत्न-विशेषज्ञ हीरे की कटाई, स्पष्टता, रंग और कैरेट को लेकर चिंतित रहते हैं, वहीं क्वांटम शोधकर्ता हीरे के "डिफेक्ट " में रुचि रखते हैं।
- हीरे में कार्बन परमाणुओं की अनोखी व्यवस्था ही उसे कठोरता, विद्युत चालकता और प्रकाश को नियंत्रित करने के गुण प्रदान करती है।
- हालाँकि, कुछ हीरों की परमाणु संरचना में कभी-कभी दो कार्बन परमाणु लुप्त होते हैं।
- इन्हें एक नाइट्रोजन परमाणु के साथ-साथ एक होल या जिसे नाइट्रोजन-रिक्ति केन्द्र कहा जाता है, द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है।
- ये "केंद्र" चुंबकीय क्षेत्र में होने वाले मामूली बदलावों के प्रति संवेदनशील होते हैं और इस प्रकार जांच के नए रास्ते खुलते हैं।
- ऐसे केन्द्र पर स्थित इलेक्ट्रॉन को व्यक्तिगत रूप से समायोजित किया जा सकता है तथा उसे क्यूबिट की तरह व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।
- क्लासिकल कंप्यूटरों के बिट्स और बाइट्स के समान क्यूबिट्स, क्वांटम कंप्यूटरों की तार्किक अवस्थाएं हैं और सिद्धांत रूप में, मौजूदा सुपर कंप्यूटरों की क्षमता से परे गणनाओं को एक पल में करने की अनुमति देते हैं।
- शोधकर्ता इन केंद्रों में हेरफेर करने के लिए कमरे के तापमान पर लेज़र का भी उपयोग कर सकते हैं।
- हालांकि, आभूषण की दुकानों में मिलने वाले हीरों के विपरीत, वैज्ञानिक प्रयोगशाला में उगाए गए हीरों को पसंद करते हैं, जिन्हें उनकी पसंद के अनुसार 'डिफेक्ट ' के साथ अनुकूलित किया जाता है।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने दशक के अंत तक 50 से 1,000 क्यूबिट के क्वांटम कंप्यूटर बनाने की योजना की घोषणा की है।
- लेकिन, वैश्विक स्तर पर क्वांटम कंप्यूटर उपयोगी उपकरण बनने से बहुत दूर हैं, क्योंकि डिफेक्ट हीरों' की तरह इलेक्ट्रॉनों को उनकी क्यूबिट जैसी अवस्था में बनाए रखना एक कठिन चुनौती है।

5. सरकार ने श्वेत वस्तुओं हेतु PLI योजना 12 अक्टूबर तक फिर से खोली - द हिंदू

प्रासंगिकता: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों का जुटाना, वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे

प्रीलिम्स टेकअवे
- उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन

समाचार:
- केंद्र ने श्वेत वस्तुओं के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना के लिए आवेदन विंडो फिर से खोल दी है, जिसका हवाला देते हुए उद्योग ने वर्ष 2021 में मूल रूप से शुरू की गई योजना में अधिक निवेश करने की इच्छा जताई है।

मुख्य बिंदु
- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने कहा कि यह नई विंडो PLI व्हाइट गुड्स (PLIWG) योजना के तहत "एयर कंडीशनर और LED लाइट के प्रमुख घटकों के विनिर्माण के कारण बढ़ते बाजार और उत्पन्न विश्वास का परिणाम है।"
- किसी भी भेदभाव से बचने के लिए, नए आवेदकों और PLIWG के मौजूदा लाभार्थियों दोनों को, जो उच्च लक्ष्य खंड में स्विच करके अधिक निवेश करने का प्रस्ताव रखते हैं, उन्हें छूट दी गई है।
  - या उनकी समूह कंपनियां अलग-अलग लक्ष्य खंड के तहत आवेदन करने के लिए पात्र होंगी।

उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI)
- PLI योजना की परिकल्पना घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने, आयात प्रतिस्थापन और रोजगार सृजन को बढ़ाने के लिए की गई थी।
- मार्च 2020 में शुरू की गई इस योजना ने शुरुआत में तीन उद्योगों को लक्षित किया:
  - मोबाइल एवं संबद्ध घटक विनिर्माण
  - विद्युत घटक विनिर्माण और
  - चिकित्सा उपकरण।
- बाद में इसे 14 सेक्टरों तक बढ़ा दिया गया।
- PLI योजना में, घरेलू और विदेशी कंपनियों को भारत में विनिर्माण के लिए पांच वर्षों तक उनके राजस्व के प्रतिशत के आधार पर वित्तीय पुरस्कार मिलता है।

6. सरकार तट से जहाज तक बिजली परियोजना का विस्तार करेगी - द हिंदू

प्रासंगिकता: इंफ्रास्ट्रक्चर: ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, हवाई अड्डे, रेलवे आदि।

प्रीलिम्स टेकअवे
- PSW
- विद्युत अधिनियम 2003

समाचार:
- बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय अपने तट से जहाज तक बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करने और नीति दिशानिर्देशों को संशोधित करने की योजना बना रहा है ताकि भारत के सभी बंदरगाहों पर बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
- प्रमुख और गैर-प्रमुख दोनों प्रकार के जहाजों के पास बड़े EXIM (निर्यात-आयात) जहाजों, तटीय जहाजों और बंदरगाह शिल्प को तटीय बिजली की आपूर्ति करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है।

मुख्य बिंदु
- चर्चा के अंतर्गत रोडमैप में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (PFC) की सहायता से संभावित वित्तपोषण योजनाएं शामिल हैं।
- बंदरगाहों के लिए वितरण लाइसेंस प्राप्त करने के लिए विद्युत मंत्रालय और राज्य डिस्कॉम को शामिल करना एक वांछनीय शर्त है।
- शिपिंग की भाषा में, तटीय बिजली से तात्पर्य किसी नाव, जहाज या किसी समुद्री जहाज को बंदरगाह पर खड़े होने पर दी जाने वाली बिजली आपूर्ति से है।
- भारत एक ऐसी व्यवस्था पर जोर दे रहा है, जिसमें जहाज बर्थ पर खड़े होने के दौरान डीजल जनरेटर पर चलने के बजाय बिजली का उपयोग कर सकें।
- इससे न केवल ईंधन की बचत होगी बल्कि बंदरगाह क्षेत्र में जहाजों से होने वाले उत्सर्जन में भी कमी आएगी।

विनियामक संरेखण
- "विद्युत अधिनियम 2003 के अनुसार, डिस्कॉम के अलावा किसी अन्य इकाई द्वारा वाणिज्यिक विद्युत पारेषण, वितरण और व्यापार की अनुमति नहीं है।
- इसलिए, बंदरगाहों को वाणिज्यिक बिजली वितरण में शामिल होने की अनुमति देने के लिए बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय (PSW) को बिजली मंत्रालय के साथ तालमेल करना होगा।

संक्रमण योजना

- इसी प्रकार, शिपिंग महानिदेशालय, भारतीय बंदरगाह संघ, विद्युत वित्त निगम तथा अन्य सहित सभी हितधारकों के साथ विस्तृत तकनीकी चर्चा का सुझाव दिया जा रहा है।
- इस सहयोगात्मक प्रयास का उद्देश्य एक ऐसी योजना के तौर-तरीकों को अंतिम रूप देना है, जिसे NBFC (इस मामले में PFC) वित्तपोषित कर सके।

एडिटोरियल, जिस्ट, एक्सप्लेनेर

7. संस्कृति मंत्रालय ने 46वीं विश्व धरोहर समिति बैठक हेतु प्रोजेक्ट PARI की शुरुआत की - पीआईबी

प्रासंगिकता: भारतीय संस्कृति - प्राचीन काल से आधुनिक काल तक कला रूपों, साहित्य और वास्तुकला के प्रमुख पहलू।
प्रसंग:

- भारत के सार्वजनिक कला स्थल हमारी लोक कला और लोक संस्कृति का प्रतिबिंब हैं। जब हम सार्वजनिक कला की बात करते हैं, तो यह बहुत गतिशील होती है और अतीत, वर्तमान और भविष्य का एक प्रतिच्छेदन होती है। इसके माध्यम से हम पारंपरिक और समकालीन जैसे विभिन्न कला रूपों में विभिन्न विचारों का समामेलन देख सकते हैं।
- तेजी से हो रहे शहरीकरण के साथ, सार्वजनिक कला विशिष्टता की भावना को बढ़ाती है तथा शहर की छवि में सौंदर्यात्मक मूल्य जोड़ती है।
- संस्कृति मंत्रालय ने विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक के अवसर पर प्रोजेक्ट PARI (भारत की सार्वजनिक कला) की शुरुआत की है।
  - इसके तहत संस्कृति मंत्रालय के अधीन स्वायत्त संस्था ललित कला अकादमी ने देश भर से 150 से अधिक दृश्य कलाकारों को आमंत्रित किया है।
  - प्रोजेक्ट PARI का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी की ऐतिहासिक विरासत में भव्यता जोड़ते हुए दिल्ली के सौंदर्य और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को उन्नत करने के लिए एक मंच प्रदान करना है।

प्रोजेक्ट PARI का महत्व	**प्रदर्शित कला रूप**
• सार्वजनिक स्थानों पर कला का प्रतिनिधित्व विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह देश की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है। • सड़कों, पार्कों और परिवहन केन्द्रों में कला को एकीकृत करके, ये पहल यह सुनिश्चित करती हैं कि कलात्मक अनुभव सभी के लिए उपलब्ध हों। • प्रोजेक्ट PARI, दिल्ली में भारत की समृद्ध और विविध कलात्मक विरासत को समाहित करने के साथ-साथ समकालीन विषयों और अभिव्यक्तियों को अपनाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है।	• रचनात्मक कैनवास में फड़ चित्रकला (राजस्थान), थंगका चित्रकला (सिक्किम/लद्दाख), लघु चित्रकला (हिमाचल प्रदेश), गोंड कला (मध्य प्रदेश), तंजौर चित्रकला (तमिलनाडु), कलमकारी (आंध्र प्रदेश), अल्पना कला (पश्चिम बंगाल), चेरियल चित्रकला (तेलंगाना), पिछवाई चित्रकला (राजस्थान), लांजिया सौरा (ओडिशा), पट्टचित्र (पश्चिम बंगाल), बानी थानी चित्रकला (राजस्थान), वारली (महाराष्ट्र), पिथौरा कला (गुजरात), ऐपण (उत्तराखंड), केरल भित्ति चित्र (केरल), अल्पना कला (त्रिपुरा) और अन्य शैलियों से प्रेरित और/या चित्रित कलाकृतियां शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। • इसके अलावा, प्रस्तावित 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक के अनुरूप, कुछ कलाकृतियां और मूर्तियां विश्व धरोहर स्थलों जैसे बिम्बेटका से प्रेरणा लेती हैं और भारत के 7 प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों को प्रस्तावित कलाकृतियों में विशेष स्थान दिया गया है। • नागरिकों को शामिल करके और एक साझा सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देकर, यह पहल न केवल शहरी परिदृश्य को समृद्ध करती है, बल्कि हमारी विरासत के साथ गहरा जुड़ाव भी उत्पन्न करती है।

8. स्वदेशी HPV वैक्सीन से संबंधित मामला - द हिंदू

प्रासंगिकता: स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।
प्रसंग:

- यह बात संदेह से परे सिद्ध नहीं है कि HPV गर्भाशय-ग्रीवा कैंसर का कारण बनता है, क्योंकि मनुष्यों को संक्रमित करने वाले 200 में से केवल कुछ ही प्रकार किसी न किसी तरह से 'कैंसर-पूर्व घावों' से 'संबद्ध' होते हैं।
- गर्भाशय-ग्रीवा कैंसर से मरने वाली अधिकांश महिलाएं HPV पॉजिटिव होती हैं, लेकिन HPV पॉजिटिव अधिकांश पुरुष और महिलाएं वायरस से प्रेरित कैंसर से ग्रस्त नहीं होते, इसके कारण उनकी मृत्यु होना तो दूर की बात है।

अनुसंधान

- भारत की जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्री (PBCR) और कैंसर पर शोध के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी (IARC) ने वैक्सीन कवरेज या प्रभावकारिता की परवाह किए बिना भारत और दुनिया में गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के प्रसार में गिरावट के रुझान को स्वीकार किया है।
- इसलिए, HPV के खिलाफ लड़कियों के 'सार्वभौमिक' टीकाकरण के लिए अति उत्साही प्रयास का समय, वायु-जनित, जल-जनित या संक्रामक रोगों के विपरीत, यौन संचरण को ध्यान में रखते हुए, उच्च जोखिम वाले समूहों के अधिक न्यायोचित 'चयनात्मक' टीकाकरण के साथ गंभीर अन्याय करता है।

वैक्सीन निर्माण का मार्ग	भारत पर प्रभाव
• सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) ने 'सर्वावैक' विकसित किया और इसे स्वदेशी और सस्ती वैक्सीन के रूप में प्रचारित किया। • सर्वावैक भी ऐसी ही तकनीक का उपयोग करता है, जिसमें HPV संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए पुनः संयोजक डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड (rDNA) तकनीक का उपयोग करके उत्पादित वायरस जैसे कणों (VLPs) का उपयोग किया जाता है। • गर्भाशय-ग्रीवा कैंसर के विरुद्ध टीका, वर्ष 1970 के दशक की शुरुआत की तकनीक का उपयोग करके बनाया गया विश्व का दूसरा rDNA टीका है, पहला टीका हेपेटाइटिस-B के विरुद्ध था। • rDNA विधियों के विकास से पहले, वैक्सीन निर्माण मुख्यतः एक धर्मार्थ या सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम था, जिसमें स्ट्रेन/तकनीक का सार्वभौमिक साझाकरण होता था तथा टीकों के पेटेंट के लिए बहुत कम या कोई स्थान नहीं था। • वर्ष 1980 के दशक में अमेरिकी पेटेंट अधिनियम में संशोधन के साथ ही पूरा परिदृश्य बदल गया, जिसके तहत आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों (GMO) और जीवन प्रक्रियाओं को पेटेंट करने की अनुमति दी गई, तथा सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित वैज्ञानिकों द्वारा कंपनियां स्थापित करने को वैध बनाने के लिए बेह-डोल अधिनियम को लागू किया गया। • वर्ष 1995 के बाद से बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधित पहलुओं पर विश्व व्यापार संगठन समझौते (TRIPS) के माध्यम से अमेरिकी पेटेंट कानूनों के अंततः वैश्वीकरण के साथ, वैक्सीन विकास और नवाचार में भारी बदलाव आया। • वैक्सीन नवाचार में संगठन, पेटेंटिंग रणनीतियों और यहां तक कि शिक्षा और उद्योग में वितरण प्रथाओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। • इस 'मूल्य संवर्धन' का एक महत्वपूर्ण तत्व सार्वजनिक 'अनुसंधान' को निजी 'विकास' में बदलने तथा पेटेंट द्वारा उस पर एकाधिकार स्थापित करने का वैधीकरण है। • इससे दुनिया भर में वैक्सीन के विकास और उत्पादन का काम सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र में स्थानांतरित हो गया, जिसे उदारीकरण और वैश्वीकरण की राजनीति से मदद मिली।	• इन घटनाक्रमों ने सामान्य रूप से भारतीय फार्मास्यूटिकल और बायोटेक उद्योग तथा विशेष रूप से वैक्सीन विकास को प्रभावित किया। • इससे पहले, भारतीय पेटेंट अधिनियम (1970) ने उत्पादों के पेटेंट को समाप्त कर दिया था और केवल प्रक्रियाओं को अनुमति दी थी, उसमें भी कृषि और जैविक पेटेंट को शामिल नहीं किया गया था। • इससे घरेलू उद्योगों के विकास को बल मिला और दो दशकों के भीतर ही वे विश्व की फार्मेसी बन गए। • उन्होंने वैश्विक स्तर पर कम लागत वाली जेनेरिक दवाओं और टीकों का निर्माण किया, अक्सर वैश्विक स्तर पर इनके आने के कुछ वर्षों के भीतर ही। • हेपेटाइटिस-बी के लिए भारत में निर्मित पहला rDNA टीका न केवल प्रक्रिया पेटेंट के तहत पांच वर्षों के भीतर बाजार में आया, बल्कि इसकी कीमत भी वैश्विक उत्तर की तुलना में काफी सस्ती हो गई। • दूसरी ओर, वर्तमान उत्पाद पेटेंट व्यवस्था के तहत, गर्भाशय-ग्रीवा कैंसर के खिलाफ स्थानीय स्तर पर निर्मित डीएनए वैक्सीन को अपने स्वदेशी 'जेनेरिक' संस्करण के उपलब्ध होने से पहले उत्पाद पेटेंट की समाप्ति तक दो दशकों तक इंतजार करना पड़ा। • जबकि बहुराष्ट्रीय पेटेंट एकाधिकार स्थानीय वैक्सीन के विकास में देरी का मुख्य कारण है, फिर भी जो बात अभी भी अस्पष्ट बनी हुई है, वह है सर्वावैक का वर्तमान बाजार मूल्य बहुत अधिक होना। • यहां तक कि निजी बाजार में घरेलू स्तर पर निर्मित टीका लगभग आधी कीमत पर भी काफी हद तक अप्राप्य है, जिससे यह टीका लक्षित आबादी के एक बड़े हिस्से की पहुंच से बाहर है। • इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि मूल्य निर्धारण की रणनीति अनुचित है, क्योंकि कीमत वास्तव में उत्पादन लागत को प्रतिबिंबित नहीं करती है। • एक अन्य गंभीर चिंता घरेलू कंपनियों की ओर से अन्य प्रतिस्पर्धी टीकों की अनुपलब्धता है, जिससे सर्वावैक की वर्तमान कीमत पर दबाव पड़ सकता है। • सर्वावैक वैक्सीन वर्तमान में सरकारी टीकाकरण कार्यक्रम के तहत नौ से 26 वर्ष की आयु की लड़कियों के लिए सार्वभौमिक रूप से अनुशंसित है, जिसकी दो खुराक की कीमत 500 रुपये है, जो सरकार के लिए भी महंगी है। • सरकारी कवरेज से वंचित रह गए उन लाखों लोगों के लिए, सर्वावैक की खुदरा कीमत चार गुना बढ़कर 2,000 रुपये हो जाएगी, वह भी ऐसे देश में जहां बीमा की पहुंच बहुत कम है और स्वास्थ्य पर जेब से होने वाला खर्च बहुत अधिक है। • इसलिए, यद्यपि गर्भाशय-ग्रीवा कैंसर की रोकथाम के लिए सार्वभौमिक HPV टीकाकरण की आवश्यकता एक अनसुलझा संदेह बना हुआ है, तथापि प्रतिस्पर्धा का अभाव और अस्पष्ट मूल्य निर्धारण व्यापक जनहित में जांच के योग्य है।

9. दिल्ली में पेड़ों की कटाई को रोकने वाले कानून -द हिंदू

प्रासंगिकता: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट, पर्यावरण प्रभाव आकलन।

प्रसंग:

- हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की अवकाश पीठ ने दिल्ली सरकार और दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) को भीषण गर्मी के बीच राष्ट्रीय राजधानी के हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए प्रभावी कदम उठाने का निर्देश दिया।

हरित आवरण का विस्तार

- भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) द्वारा प्रकाशित 'भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021' (ISFR) के अनुसार, दिल्ली में सात प्रमुख महानगरों में सबसे बड़ा वन आवरण है
- दिल्ली का वन क्षेत्र उसके भौगोलिक क्षेत्र का 13.15% है, जबकि वृक्ष क्षेत्र 147 वर्ग किमी (9.91%) है।
- व्यापक शहरी विकास के बावजूद, शहर का समग्र हरित आवरण (वन और वृक्ष आवरण) वर्ष 2001 में 151 वर्ग किमी (10.2%) से बढ़कर 2021 में 342 वर्ग किमी (23.6%) हो गया है।

संरक्षण	मामला क्या है?
• दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम (DPTA), 1994 राष्ट्रीय राजधानी में वृक्षों को उन कार्यों के विरुद्ध कानूनी संरक्षण प्रदान करता है, जो उनकी वृद्धि या पुनर्जनन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। • अधिनियम की धारा 2 (h) के अनुसार, "पेड़ गिराने" में तने को जड़ से अलग करना, उखाड़ना, बुलडोजर से गिराना, काटना, घेरा बनाना, छंटाई करना, वृक्षनाशकों का प्रयोग करना, जलाना या कोई अन्य नुकसानदायक तरीका शामिल है। • धारा 8 के तहत, किसी भी भूमि पर 'वृक्ष अधिकारी' की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी वृक्ष या वन उपज नहीं हटाई जा सकती, यहां तक कि निजी स्वामित्व वाली संपत्ति पर भी नहीं। • 'वृक्ष अधिकारी' निरीक्षण के बाद अनुमति दे सकता है और उसे 60 दिनों के भीतर जवाब देना होगा। • इस अधिनियम का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को एक वर्ष तक का कारावास, 1,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है। • इसके अलावा, अधिनियम में एक 'वृक्ष प्राधिकरण' की रूपरेखा दी गई है, जिसका कार्य अन्य जिम्मेदारियों के अलावा वृक्षों की गणना करना, नर्सरियों का प्रबंधन करना, तथा सरकारी और निजी निर्माण प्रस्तावों की समीक्षा करना है। • इसके अलावा, दिल्ली की वृक्ष प्रत्यारोपण नीति, 2020 में यह अनिवार्य किया गया है कि काटे जाने वाले चिन्हित वृक्षों में से 80% वृक्षों का प्रत्यारोपण किया जाना चाहिए। • हालाँकि, वर्ष 2022 में सरकार द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में प्रस्तुत एक हलफनामे में खुलासा किया गया कि नीति की अधिसूचना के बाद से प्रत्यारोपित किए गए 16,461 पेड़ों में से केवल 33.33% ही जीवित बचे हैं।	• सर्वोच्च न्यायालय DDA के उपाध्यक्ष सुभाशीष पांडा के खिलाफ अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें रिज क्षेत्र में सड़क विस्तार के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हुए लगभग 1,100 पेड़ों को गिराने का आरोप है। रिज क्षेत्र पारिस्थितिकी दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र के अंतर्गत आता है। • DDA ने गौशाला रोड के निर्माण के लिए पेड़ों को काटने की अनुमति मांगते हुए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन प्रस्तुत किया। • हालांकि, अदालत ने DDA को क्षेत्र के विशेषज्ञों की मदद से प्रस्ताव की पुनः जांच करने का निर्देश दिया। • फरवरी तक, आवेदन सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने से पहले ही सभी प्रस्तावित पेड़ काट दिए गए थे। • यह जानते हुए भी कि न्यायालय की अनुमति के बिना किसी भी पेड़ को नहीं छुआ जा सकता, DDA ने न्यायालय को गुमराह किया तथा पेड़ों की कटाई के बाद ही अनुमति मांगकर दुर्भावना से काम किया। • सर्वोच्च न्यायालय ने DDA के काम पर रोक लगा दी है और FSI की एक टीम को काटे गए पेड़ों की संख्या और पर्यावरण को हुए नुकसान का आकलन करने का निर्देश दिया है।

आगे की राह

- प्रचंड गर्मी के बीच, दुनिया के दूसरे सबसे अधिक आबादी वाले शहर में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई से मुश्किलें और बढ़ेंगी।
- शहरी वन कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं, उत्सर्जन को अवशोषित करते हैं और प्रदूषकों को छानते हैं, जो दिल्ली जैसे शहरों के लिए आवश्यक है, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक लगातार अस्वस्थ बना हुआ है।
- पेड़ छाया और वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से तापमान को कम करके शहरी ऊष्मा द्वीप प्रभाव को कम करते हैं।
- अन्य सुधारों के अलावा, सरकार को वर्तमान वास्तविकताओं के अनुरूप DPTA., 1994 के अंतर्गत जुर्माने की राशि को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये करने पर विचार करना चाहिए।

10. सरकार को स्वास्थ्य बजट को दोगुना करना चाहिए - द हिंदू

प्रासंगिकता:स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

प्रसंग:

- एक लक्ष्य जो लगातार बदलता रहता है, वह है सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के 2.5% के आंकड़े तक बढ़ाना।
- वर्तमान में, सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय लगभग 1.35% है। कम सार्वजनिक व्यय का अर्थ है परिवारों द्वारा अधिक जेब से किया जाने वाला व्यय।
- जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 13.4% परिवारों ने और शहरी क्षेत्रों में 8.5% परिवारों ने चिकित्सा बिलों का भुगतान करने के लिए धन उधार लिया, शेष परिवारों ने मुफ्त सार्वजनिक देखभाल की मांग की।

गरीबी रेखा से नीचे

- अनुमान है कि 60-80 मिलियन परिवार चिकित्सा देखभाल का लाभ उठाने के मामले में गरीबी रेखा से नीचे हैं। भारतीय राजनीति का विरोधाभास यह है कि इन सबके बावजूद, निर्वाचित सरकारों के लिए स्वास्थ्य कोई मुद्दा नहीं है।
- भारत की स्वास्थ्य प्रणाली एक ऐसे स्थिति में है, जहां बिना किसी विलंब के सभी राज्यों, विशेषकर उत्तरी राज्यों में, रोग के दोहरे बोझ से निपटने के लिए क्षमता का निर्माण करना आवश्यक है।

- संक्रामक एवं संक्रामक रोगों को रोग की प्रासंगिक प्रकृति के कारण संभालना आसान होता है, हालांकि, यदि इनकी उपेक्षा की जाए तो परिणाम विनाशकारी एवं क्रूर हो सकते हैं।
- दूसरी ओर, गैर-संचारी रोगों का प्रबंधन जीवन भर करना पड़ता है, जिसके लिए एक स्थिर, नियमित देखभाल प्रणाली की आवश्यकता होती है।
- इन दोनों से निपटने के लिए एक ऐसी स्वास्थ्य प्रणाली की आवश्यकता है जो तेज और सक्रिय होने के साथ-साथ स्थिर और ठोस भी हो।
- सही संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है: कौशल और योग्यता, प्रौद्योगिकी, इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यवेक्षी प्रणालियों का सही मिश्रण। इन सबके लिए धन की आवश्यकता होती है।
- वर्ष 2010 से भारत का सार्वजनिक व्यय जीडीपी के अनुपात में 1.12% से 1.35% के बीच रहा है।सकल रूप में, हालांकि केंद्रीय बजट आवंटन में निश्चित रूप से सुधार हुआ है, जो वर्ष 2012-13 में ₹25,133 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹86,175 करोड़ हो गया है, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य बजट का सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में लगभग 0.27% रहा है।
- राज्यों द्वारा अपने राजस्व बजट का औसतन 5% व्यय करने के लक्ष्य के मुकाबले, बिहार जैसे गरीब राज्यों में समग्र सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय न केवल कम है, बल्कि अनुपातहीन रूप से कम है।
- हालांकि कुल मिलाकर आवंटन निराशाजनक रहा है, लेकिन हाल ही में विश्व बैंक से 65 मिलियन डॉलर और ADB से 175 मिलियन डॉलर का ऋण एक सकारात्मक पहल है, जिस पर बातचीत हुई है। इसके तहत, जिला स्तरीय रोग निगरानी प्रयोगशाला के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, बड़े जिलों में ICU स्थापित करने, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को मजबूत करने आदि पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो सही भी है।
- भारत को देश में बुनियादी स्वास्थ्य ढांचे के निर्माण में भारी और तेजी से निवेश करने की जरूरत है, खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और असम राज्यों में।
  - जहां सुविधाओं के साथ-साथ मानव संसाधनों की कमी राष्ट्रीय औसत 30% से कहीं अधिक है।
- जब तक आपूर्ति की स्थिति में सुधार नहीं होता, आयुष्मान भारत (PMJAY) जैसे मांग-पक्ष हस्तक्षेप सीमांत मूल्य के हैं, खासकर तब, जब आउट-पेशेंट देखभाल का बीमा नहीं किया जाता है।
- इन राज्यों में सिस्टम विकसित किए जाने चाहिए और वित्त मंत्रालय को न केवल स्वास्थ्य बजट में पर्याप्त वृद्धि करके, विशेष रूप से NHM के लिए, बल्कि इसके अलावा, 4% स्वास्थ्य उपकर के तहत एकत्र किए गए सभी धन को स्वास्थ्य बजट में आवंटित करके इसकी शुरुआत करनी चाहिए।
  - अब तक एकत्र किए गए कुल ₹69,063 करोड़ में से, इसका केवल 25% स्वास्थ्य मंत्रालय को हस्तांतरित किया गया है।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने के अलावा, स्वास्थ्य उत्पादों पर GST शुल्क को तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता है, जैसे कि स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर 18% GST या इंसुलिन और हेपेटाइटिस डायग्नोस्टिक्स पर 5% GST , जब मधुमेह रोगियों और हेपेटाइटिस से ग्रस्त लोगों की संख्या बढ़ रही है।
- उन निजी संस्थाओं के लिए भी हतोत्साहन पर विचार करने की आवश्यकता है जो पूर्ण GST छूट और समय-समय पर दी जाने वाली बड़ी संख्या में अन्य रियायतों के बावजूद देखभाल की लागत बढ़ा रही हैं।
- हालाँकि, स्वास्थ्य क्षेत्र के संबंध में मुख्य बात राज्य की भूमिका, कर-भुगतान करने वाले नागरिकों के अधिकार और प्रस्तावित विकास मॉडल पर आधारित है।
- क्या स्वास्थ्य एक सार्वजनिक वस्तु है? क्या स्वस्थ जीवन मानव विकास के लिए एक आधारभूत शर्त है? क्या स्वास्थ्य सामाजिक अनुबंध का हिस्सा है जो नागरिकों का राज्य के साथ तब होता है जब वे टैक्स चुकाते हैं? क्या बीमार लोगों की मदद करना एक सामाजिक दायित्व है? यदि उत्तर हाँ में है, तो सरकार के लिए स्वास्थ्य बजट को दोगुना करने के साथ-साथ एक सुधार एजेंडा शुरू करने का समय आ गया है ताकि एक बेकार प्रणाली को ठीक किया जा सके।
- इसमें समय लगता है, राजनीतिक सहमति की आवश्यकता होती है और अस्थिर राजनीतिक माहौल के कारण इसे बाधित या बाधित नहीं किया जाना चाहिए। अन्य देशों ने रास्ता दिखाया है। भारत को अब वर्ष 2047 तक विकसित देश बनने की आकांक्षा को विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए उनके मार्ग का अनुसरण करने की आवश्यकता है।

फैक्ट फटाफट

1. आनंद विवाह अधिनियम

- आनन्द विवाह अधिनियम, जो मूलतः 1909 में पारित हुआ था, भारत में सिख समुदाय के लिए विशेष रूप से बनाया गया एक कानूनी अधिनियम है।
- यह अधिनियम सिख विवाहों को हिंदू विवाहों से अलग कानूनी मान्यता प्रदान करने के लिए बनाया गया था।
- सिख समुदाय में इसे 'आनंद कारज' कहा जाता है।
- यह अधिनियम आनंद कारज समारोह के महत्व को स्वीकार करता है, जो सिख वैवाहिक अनुष्ठानों का केंद्र है और समुदाय की अनूठी धार्मिक प्रथाओं को दर्शाता है।

2. अग्निबाण सबऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोस्ट्रेटर (SOrTeD)

- यह अग्निकुल के पेटेंटेड अग्निलेट इंजन द्वारा संचालित एकल-चरण प्रक्षेपण यान है।
- यह पूर्णतः 3D-मुद्रित, एकल-टुकड़ा, 6 किलोन्यूटन (kN) अर्ध-क्रायोजेनिक इंजन है।
- यह विश्व का पहला एकल टुकड़ा 3D मुद्रित अर्ध-क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है।
- इसे भारत के पहले निजी लॉन्चपैड, ALP-01 से लॉन्च किया जाएगा, जो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के श्रीहरिकोटा अंतरिक्षयान में स्थित है।
- यह भारत का पहला वाहन है जो अर्ध क्रायोजेनिक इंजन से सुसज्जित है। अग्निलेट एक उपशीतित तरल ऑक्सीजन आधारित प्रणोदन प्रणाली है जिसे स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है।

3. परमाणु ऊर्जा आयोग

- परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना सर्वप्रथम अगस्त 1948 में वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग में की गई थी, जिसे कुछ महीने पहले जून 1948 में बनाया गया था।
- भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना पहली बार अगस्त 1948 में डॉ. होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में की गई थी, जो एक प्रसिद्ध भारतीय भौतिक विज्ञानी थे और जिन्हें भारत के परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है।
- परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 3 अगस्त, 1954 को राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रभार में की गई थी।
- आयोग की स्थापना शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने तथा देश में परमाणु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देने के प्राथमिक उद्देश्य से की गई थी।

4. करम्पुआंग गुफा

- यह इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर स्थित एक चूना पत्थर की गुफा है।
- गुफा की दीवार पर एक सूअर के साथ बातचीत करते हुए मनुष्य का दृश्य चित्रित है।
- इस दृश्य में एक सूअर को दर्शाया गया है जो तीन छोटी मानव जैसी आकृतियों के साथ सीधा खड़ा है, तथा इसे गहरे लाल रंग के एक ही शेड से चित्रित किया गया है।
- एक आकृति सुअर के गले के पास कोई वस्तु पकड़े हुए दिखती है। दूसरी आकृति सुअर के सिर के ठीक ऊपर उल्टी अवस्था में है और उसके पैर फैले हुए हैं।
- तीसरी आकृति अन्य की तुलना में बड़ी और भव्य है; यह एक अज्ञात वस्तु पकड़े हुए है और संभवतः एक विस्तृत सिर-वस्त्र पहने हुए है।
- यह चित्रकला यूरोप की गुफा चित्रकला से भी पुरानी है, जो स्पेन के एल कैस्टिलो में है, तथा लगभग 40,800 वर्ष पुरानी है।

5. शास्त्रीय भाषा

- संस्कृति मंत्रालय शास्त्रीय भाषाओं के बारे में दिशा-निर्देश प्रदान करता है। भारत में शास्त्रीय भाषाएँ संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध हैं। राज्यसभा के संस्कृति मंत्रालय ने फरवरी 2014 में किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में नामित करने के लिए मानदंड जारी किए।
- भारत में अभी छह शास्त्रीय भाषाएँ हैं - तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया।
- शास्त्रीय भाषा से प्राप्त लाभों में निम्नलिखित शामिल हैं:
  - महत्वपूर्ण वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किये गए।
  - शास्त्रीय भारतीय भाषा अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना
  - विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शास्त्रीय भाषाओं के लिए विशिष्ट संख्या में व्यावसायिक पीठों का सृजन किया जाना है, जिसकी शुरुआत कम से कम केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से की जाएगी।

प्रीलिम्स ट्रैक

Q1. महिला उद्यमिता मंच के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. यह क्रिसिल द्वारा महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स के ऋण मूल्यांकन और संभावित इक्विटी निवेश जैसी अनूठी सेवाएं प्रदान करता है।
2. इसका उद्देश्य गतिशील नए भारत के निर्माण और उसे सशक्त बनाने के लिए महिला उद्यमियों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि करना है।
3. यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक नया कार्यक्रम है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 1 और 3
C. 1, 2 और 3
D. केवल 2 और 3

Q2. भारत में शास्त्रीय भाषाओं और भाषाई अधिकारी की भूमिका के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. तेलुगु भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित की जाने वाली पहली भाषा थी।
2. किसी भाषा को शास्त्रीय तब कहा जाता है जब उसके पास समृद्ध विरासत और स्वतंत्र प्रकृति हो, तथा जिसमें प्राचीन साहित्य या ग्रंथों का विशाल भंडार हो।
3. भाषाई अधिकारी की प्राथमिक भूमिका क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों के प्रयोग और विकास को बढ़ावा देना है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1 और 3
D. 1, 2 और 3

Q3. संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (UNCLOS) और समुद्री जैव विविधता के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. UNCLOS विश्व के समुद्रों और महासागरों के उपयोग के लिए दिशानिर्देश स्थापित करता है, तथा समुद्री संसाधनों के संरक्षण और न्यायसंगत उपयोग को सुनिश्चित करता है।
2. यह सम्मेलन तटीय राज्यों के अपने विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) के संसाधनों पर संप्रभुता अधिकारों को मान्यता देता है, जो उनकी आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक फैला हुआ है।
3. UNCLOS के तहत स्थापित अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण (ISA) राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल क्षेत्र, जिसे "क्षेत्र" के रूप में जाना जाता है, में खनिज संबंधी गतिविधियों को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1 और 3
D. 1, 2 और 3

Q4. निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ "क्यूबिट" शब्द का उल्लेख करता है?

A. क्लाउड सेवाएं
B. क्वांटम कम्प्यूटिंग
C. दृश्य प्रकाश संचार प्रौद्योगिकियां
D. वायरलेस संचार प्रौद्योगिकियां

Q5. उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. इसका उपयोग रोजगार सृजन, सामाजिक कल्याण और कराधान के लिए आवश्यक मानी जाने वाली वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है
2. यह कर छूट, आयात और निर्यात शुल्क में कमी या व्यवसायों के लिए अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए आसान भूमि अधिग्रहण मानदंडों के रूप में हो सकता है
3. इसे वस्तुओं के आयात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा पहचाने गए 13 क्षेत्रों में लॉन्च किया गया है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2
B. 2 और 3
C. केवल 1 और 3
D. 1, 2 और 3

Q6. प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. इसका उद्देश्य देश भर के सभी ग्रामीण घरों तक बिजली उपलब्ध कराना है।
2. यह योजना ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग पर केंद्रित है।
3. प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का कार्यान्वयन विद्युत मंत्रालय की जिम्मेदारी है।
4. यह योजना सौर ऊर्जा चालित उपकरणों की स्थापना के लिए परिवारों को 100% वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही है/हैं?

A. केवल एक
B. केवल दो
C. केवल तीन
D. सभी चारों

Q7. भारत की कला और संस्कृति के संदर्भ में, भारतीय चित्रकला परंपराओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. पहाड़ी चित्रकला शैली अपने लघु चित्रों के लिए जानी जाती है, जिनमें हिंदू पौराणिक कथाओं, विशेषकर राधा और कृष्ण की प्रेम कहानियों के विषयों को दर्शाया जाता है।
2. तंजौर (तंजावुर) चित्रकला शैली की विशेषता है इसमें समृद्ध रंगों का प्रयोग, सतह की समृद्धि, सुसंयोजित संरचना, तथा सरल प्रतीकात्मक रूपों पर जोर दिया जाता है।
3. बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, भारत में ब्रिटिश कला संस्थानों द्वारा प्रचारित अकादमिक कला शैलियों के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में उभरा तथा इसने पारंपरिक भारतीय कला रूपों को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1 और 3
D. 1, 2 और 3

Q8. भारत में HPV (ह्यूमन पेपिलोमावायरस) वैक्सीन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. HPV वैक्सीन का प्रयोग मुख्यतः गर्भाशय-ग्रीवा कैंसर को रोकने के लिए किया जाता है।
2. यह टीका लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए अनुशंसित है।
3. भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में वर्तमान में HPV टीका शामिल है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 1 और 3
C. केवल 2 और 3
D. 1, 2 और 3

Q9. भारत वन स्थिति रिपोर्ट (ISFR) 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. ISFR 2021 रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) द्वारा प्रकाशित की जाती है।
2. ISFR 2021 के अनुसार, भारत में कुल वन क्षेत्र पिछले आकलन की तुलना में बढ़ गया है।
3. रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में मैंग्रोव आवरण में उल्लेखनीय गिरावट आई है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 1 और 3
C. केवल 2 और 3
D. 1, 2 और 3

Q10. भारत में स्वास्थ्य व्यय के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत सरकार ने 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के 2.5% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है।
2. भारत में परिवारों द्वारा अपनी जेब से किया जाने वाला व्यय कुल स्वास्थ्य व्यय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
3. आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य अस्पताल में होने वाली भयावह घटनाओं के कारण गरीब और कमजोर वर्ग पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम करना है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1 और 3
D. 1, 2 और 3

प्रीलिम्स ट्रैक उत्तर

उत्तर : 1 विकल्प A सही है.

व्याख्या

महिला उद्यमिता मंच:

- यह CRISIL द्वारा महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स के क्रेडिट मूल्यांकन और DICE डिस्ट्रिक्ट्स द्वारा स्थापित 10 करोड़ रुपये के फंड के माध्यम से संभावित इक्विटी निवेश जैसी अनूठी सेवाएं प्रदान करता है। **(इसलिए कथन 1 सही है)**
- WEP का लक्ष्य महिला उद्यमियों के लिए विकास और अवसर के रास्ते खोलकर गतिशील नए भारत का निर्माण और सशक्तिकरण करने के लिए महिला उद्यमियों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि करना है । **(अतः कथन 2 सही है)** महिला उद्यमियों की ये आकांक्षाएं तीन स्तंभों में अभिव्यक्त होती हैं जिन पर WEP का निर्माण किया गया है:
  - इच्छा शक्ति: इच्छुक उद्यमियों को अपना उद्यम शुरू करने के लिए प्रेरित करना।
  - ज्ञान शक्ति: महिला उद्यमियों को उद्यमिता को बढ़ावा देने में सहायता के लिए ज्ञान और पारिस्थितिकी तंत्र सहायता प्रदान करना।
  - कर्म शक्ति: उद्यमियों को व्यवसाय स्थापित करने और बढ़ाने में व्यावहारिक सहायता प्रदान करना।
- यह नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया एक नया कार्यक्रम है।**(अतः कथन 3 गलत है)**

उत्तर : 2 विकल्प B सही है

व्याख्या :

- तमिल 2004 में भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित की जाने वाली पहली भाषा थी। **कथन 1 सही है।**
- किसी भाषा को उसकी प्राचीनता, समृद्ध विरासत और स्वतंत्र प्रकृति तथा प्राचीन साहित्य या ग्रंथों के विशाल भंडार के आधार पर शास्त्रीय कहा जाता है। **कथन 2 सही है।**
- भाषाई अधिकारी की प्राथमिक भूमिका में क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों का प्रचार, विकास और संरक्षण शामिल है। वे भाषा नीति कार्यान्वयन, अनुवाद और भाषा मानकीकरण पर भी काम कर सकते हैं। **कथन 3 सही है।**

उत्तर : 3 विकल्प D सही है

व्याख्या :

- संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (UNCLOS) समुद्र के संसाधनों और महासागर के उपयोग के सभी पहलुओं को विनियमित करने के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा स्थापित करता है। इसका उद्देश्य समुद्री संसाधनों का संरक्षण और न्यायसंगत उपयोग सुनिश्चित करना है। **कथन 1 सही है।**
- UNCLOS के अनुसार, तटीय राज्यों को अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में प्राकृतिक संसाधनों, चाहे वे जीवित हों या निर्जीव, की खोज और दोहन, संरक्षण और प्रबंधन के उद्देश्य से संप्रभु अधिकार प्राप्त हैं, जो उनके आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक फैला हुआ है। **कथन 2 सही है।**
- अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण (ISA) की स्थापना UNCLOS के तहत अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल क्षेत्र में खनिज संबंधी गतिविधियों को विनियमित करने के लिए की गई थी, जिसे "क्षेत्र" के रूप में जाना जाता है, जो राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र की सीमाओं से परे है। ISA यह सुनिश्चित करता है कि क्षेत्र के संसाधनों से होने वाले लाभ सभी देशों के बीच समान रूप से साझा किए जाएं। **कथन 3 सही है।**

उत्तर : 4 विकल्प B सही है.

व्याख्या

- क्यूबिट (या क्वांटम बिट) शास्त्रीय बिट का क्वांटम यांत्रिक अनुरूप है।
- शास्त्रीय कंप्यूटिंग में सूचना को बिट्स में एनकोड किया जाता है, जहां प्रत्येक बिट का मान शून्य या एक हो सकता है।
- क्वांटम कंप्यूटिंग में सूचना को क्यूबिट में एनकोड किया जाता है।
- क्यूबिट 0 या 1 की अवस्था में हो सकते हैं या (क्लासिकल बिट के विपरीत) दोनों अवस्थाओं के रैखिक संयोजन में हो सकते हैं। इस परिघटना का नाम सुपरपोजिशन है। **विकल्प B सही है।**

उत्तर : 5 विकल्प A सही है

व्याख्या

- उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन एक पारंपरिक और लोकप्रिय रणनीति है जिसका उपयोग सरकारें रोजगार सृजन, सामाजिक कल्याण और कराधान के लिए आवश्यक मानी जाने वाली वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए करती हैं। **(इस प्रकार कथन 1 सही है)**
- पीएलआई मूलतः व्यवसायों को अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन हैं।

- वे कर छूट, कम आयात और निर्यात शुल्क या आसान भूमि अधिग्रहण मानदंडों के रूप में आ सकते हैं। **(इस प्रकार कथन 2 सही है)**
- पीएलआई योजना का लाभ आम तौर पर कम लागत के रूप में वस्तुओं के अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है।
- यह योजना सरकार द्वारा चिन्हित 13 क्षेत्रों में शुरू की गई है, जिसका कुल परिव्यय लगभग 2 लाख करोड़ रुपये है, ताकि वस्तुओं के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। **(अतः कथन 3 गलत है)**

उत्तर : 6 विकल्प B सही है

व्याख्या

- प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को चौबीसों घंटे बिजली की आपूर्ति प्रदान करना है, जिससे सभी के लिए बिजली की पहुँच सुनिश्चित हो सके। **इसलिए, कथन 1 सही है**
- प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली उपलब्ध कराने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करना है। इसमें सौर ऊर्जा संयंत्रों और स्टैंडअलोन सौर प्रणालियों की स्थापना शामिल है। **इसलिए, कथन 2 सही है**
- प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का क्रियान्वयन नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) के अंतर्गत आता है, न कि विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत। **इसलिए, कथन 3 गलत है**
- हालांकि यह योजना वित्तीय सहायता प्रदान करती है, लेकिन यह पूरी लागत को कवर नहीं कर सकती है। वित्तीय सहायता का स्तर अलग-अलग होता है, और लाभार्थियों को एक निश्चित राशि का योगदान करने की आवश्यकता हो सकती है। **इसलिए, कथन 4 गलत है**

उत्तर : 7 विकल्प D सही है

व्याख्या

- पहाड़ी शैली भारतीय लघु चित्रकला की एक उल्लेखनीय शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों, विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर में हुई थी। ये पेंटिंग अपने नाजुक ब्रशवर्क, जीवंत रंगों और जटिल विवरणों के लिए जानी जाती हैं। वे अक्सर हिंदू पौराणिक कथाओं, विशेष रूप से राधा और कृष्ण की प्रेम कहानियों, साथ ही रामायण और महाभारत के दृश्यों से विषयों को दर्शाते हैं। **कथन 1 सही है।**
- तंजौर पेंटिंग एक शास्त्रीय दक्षिण भारतीय चित्रकला शैली है जिसकी उत्पत्ति तमिलनाडु के तंजावुर (तंजौर) शहर से हुई है। ये पेंटिंग अपने समृद्ध रंगों, सघन रचना और सतही समृद्धि के लिए जानी जाती हैं। वे आम तौर पर हिंदू देवी-देवताओं को चित्रित करते हैं और चमकदार प्रभाव पैदा करने के लिए सोने की पन्नी के उपयोग की विशेषता रखते हैं। **कथन 2 सही है।**
- बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट एक प्रभावशाली कला आंदोलन था जो 20वीं सदी की शुरुआत में बंगाल में शुरू हुआ था। यह भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक कला संस्थानों द्वारा प्रचारित अकादमिक कला शैलियों के खिलाफ एक प्रतिक्रिया के रूप में उभरा। **कथन 3 सही है।**

उत्तर : 8 विकल्प A सही है

व्याख्या

- HPV वैक्सीन का उपयोग मुख्य रूप से गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर को रोकने के लिए किया जाता है। **कथन 1 सही है।**
- HPV से संबंधित बीमारियों को रोकने के लिए लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए इस टीके की सिफारिश की जाती है। **कथन 2 सही है।**
- अभी तक भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में HPV वैक्सीन शामिल नहीं है। **कथन 3 गलत है।**

उत्तर : 9 विकल्प A सही है

व्याख्या

- ISFR 2021 रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) द्वारा प्रकाशित की जाती है। **कथन 1 सही है।**
- ISFR 2021 के अनुसार, भारत में कुल वन क्षेत्र पिछले आकलन की तुलना में बढ़ा है। **कथन 2 सही है।**
- रिपोर्ट बताती है कि भारत में मैंग्रोव कवर में कोई उल्लेखनीय गिरावट नहीं आई है, बल्कि इसमें वृद्धि हुई है। **कथन 3 गलत है।**

उत्तर : 10 विकल्प D सही है

व्याख्या

- भारत सरकार ने वास्तव में 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के 2.5% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। यह लक्ष्य इसकी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का हिस्सा है। **कथन 1 सही है।**
- भारत में, परिवारों द्वारा अपनी जेब से किया जाने वाला खर्च कुल स्वास्थ्य व्यय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह उच्च जेब से किया जाने वाला खर्च अक्सर वित्तीय कठिनाई और गरीबी का कारण बनता है। **कथन 2 सही है।**

GEO IAS

It's about quality

ABOUT US

GEO IAS is the best institute for civil services in India for providing top quality teaching and materials, offering you most optimum path for your success in Civil Services exam. Our aim is to provide quality training with an affordable fee structure. Our uniquely designed course make us the best institute for UPSC to crack the exam in one go. We have a dedicated team of experienced and young teachers and counsellors who make sure that every student who joins the institute, must get customized way of preparation which matches with student's learning style.
The only institute of UPSC in India which has 3 AI enabled Mobile apps. We believe in Smart way of teaching and learning. The classes are available in offline as well as in online mode. We take the help of animation so that you may visualize the lectures. Unlimited tests for prelims and mains with solution in both form (Hard copy and soft copy). We have the set of 15 lac mcqs on each topic. We provide daily news analysis, Highlighted news paper and links of important Sansad TV shows. The institute has best success rate with more than 230 students have cleared the exam. HIGHEST RATED INSTITUTE as per GOOGLE, SULEKHA and JUST DIAL and the magazine on civil services

+91-9477560001 /002/005

BRANCH: Delhi Kolkata, Raipur, Patna | HEAD OFFICE: 641, Ramlal Kapoor Marg, Mukherjee Nagar, Delhi, 110009

info@geoias.com

www.geoias.com